Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.5, December, 2024

जी-20 घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का द्योतक

डॉ रेखा रानी
इंडिपेंडेंट स्कॉलर

****

सारांश:- *एशियाई वित्तीय संकट के समय गठित सन **1999** में वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थायित्व आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु ,व्यवस्थित औद्योगीकृत, विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित् मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा मिलकर जी-**20** समूह की स्थापना की गई थी। अपने प्रारंभिक समय से ही जी-**20** समूह द्वारा नियमित रूप से वित् मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकों का आयोजन वैश्विक वित्तीय संवर्धन तथा स्थायित्व बढ़ाने के उपायों को को प्रोत्साहित करने और सतत् आर्थिक वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से किया जा रहा है । भारत ने **1** दिसंबर, **2022** को इंडोनेशिया से जी-**20** समूह की अध्यक्षता ग्रहण की और एक वर्ष तक इस पद पर रहेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में, भारत का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पहचान करना, उसे उजागर करना, बनाना और उसे गहरा करना भारत जी-**20** शिखर सम्मेलन में समावेशी विकास और विकास को उजागर करना चाहता है, जो जी-**20** चर्चाओं के सार में महिला सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। इस लेख का उद्देश्य जी-**20** शिखर सम्मेलन में भारत के संदर्भ में देश की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करना है। वर्तमान अध्ययन पुस्तकों, सरकारी प्रकाशनों, ओपन-सोर्स डेटाबेस और अन्य साहित्य स्रोतों से द्वितीयक डेटा का उपयोग करके किया गया है। यह वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों शोध पद्धतियों पर आधारित है।*

मुख्य शब्द:- *औद्योगीकृत, विकसित, व्यवस्थित, समावेशी, न्यायसंगत*

****

1. परिचय

विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद के साथ-साथ ब्रेटन वुड्स संस्थान और जी 7 उस विश्व व्यवस्था को दर्शाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रचलित हुई थी और साथ ही इसके विजेताओं द्वारा बनाए गए नए शक्ति संतुलन को भी दर्शाते हैं। जी 20 एक उभरती हुई व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जो जी 7 को अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ समान भागीदार के रूप में एक साथ लाता है। इसमें अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ पी 5 भी शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र के रूप में परिकल्पित, जी-20, जिसमें सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, समय के साथ सबसे शक्तिशाली आर्थिक और वित्तीय समूहों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में, इसमें वैश्विक सकल घरेलू

उत्पाद का 85ः, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75ः और वैश्विक आबादी का दो/तिहाई हिस्सा शामिल है। यह वैश्विक आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए दुनिया का प्रमुख निकाय है। वर्ष 2011 से वार्षिक आधार पर रोटेशनल प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित, जी20 का प्रारंभिक ध्यान व्यापक मैक्रो-इकोनॉमिक नीति पर था। औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाने वाला जी20 महामारी तक मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास हासिल करने की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है। महामारी के बाद इसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। हाल ही में, जी20 का ध्यान जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद-रोधी और प्रवासन सहित वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए स्थानांतरित हो गया। जी-20 की संरचना क्या है? इसमें 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका) और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। यह एक प्रासंगिक और प्रभावशाली वैश्विक समूह बन गया है। जी-20 प्रक्रिया में आमंत्रितों के रूप में अफ्रीकी संघ, नेपाड और आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की नियमित भागीदारी इसे समावेशी और प्रतिनिधि दोनों बनाती है। जी-20 का आरंभिक ध्यान वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर था। जब से इसे राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक बढ़ाया गया है, तब से जी-20 हर समकालीन मुद्दे और चुनौती का समाधान करने के लिए विकसित हुआ है। शेरपा और वित्त ट्रैक्स के बीच 20 कार्य समूह और 10 सहभागिता समूह हैं, जो सदस्य देशों के नागरिक समाजों, थिंक टैंकों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाते हैं। जी20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। इसकी शुरुआत 1990 के दशक के उत्तरार्ध के आर्थिक संकटों के जवाब में हुई थी; इसने ग्रुप ऑफ़ सेवन जिसे इसके राजनीतिक अवतार में ग्रुप ऑफ़ आठ के नाम से जाना जाता है के काम को आगे बढ़ाया और उन देशों को शामिल किया जो पहले वैश्विक चर्चा से बाहर रह गए थे। 2008 से, यह कम से कम साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के राज्य या सरकार के प्रमुख, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं; ईयू का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करते हैं। जी-20 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक नीति के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के उद्देश्य से की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसमें "ब्रेटन

वुड्स जुड़वाँ‘, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अब विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थान शामिल हैं। जी-20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और नेताओं को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। समावेशी वैश्विक विकास और वृद्धि के लिए सक्षम वातावरण बनाने में जी-20 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, विकास को बढ़ावा देने और संकटों को रोकने और प्रबंधित करने के इसके प्रयास अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं . जी-20 का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर चर्चा करना है। जी-20 का उद्देश्य दुनिया भर में सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना भी है। जी-20 ने 2008 के वित्तीय संकट के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तब से वैश्विक आर्थिक शासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना जारी रखा है। जी-20 का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर चर्चा करना है। जी-20 का उद्देश्य दुनिया भर में सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना भी है।

2.अध्ययन का महत्व

जी-20 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ अपने काम को और अधिक संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को प्राप्त करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तरों पर सामूहिक और व्यक्तिगत ठोस कार्रवाइयों के माध्यम से साहसिक परिवर्तनकारी कदम उठाकर 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में योगदान दिया है। ये कार्रवाइयां सतत विकास परिणामों को आगे बढ़ा सकती हैं, कम आय वाले और विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार 2030 एजेंडा को लागू करने में सहायता कर सकती हैं और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान को सक्षम कर सकती हैं। जी-20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां इसका तुलनात्मक लाभ है और आर्थिक सहयोग के लिए वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी-20 का तुलनात्मक लाभ इसकी संयोजक शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की सामूहिक क्षमता में निहित है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शामिल है, और एक वैश्विक सक्षम वातावरण बनाने के लिए।

3. समस्या का विवरण

जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक होगा। जी-20 के थिंक 20 सहभागिता समूह की गतिविधियाँ और विचार-विमर्श सात टास्क फोर्स में फैले हुए हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता अवधि के एजेंडे की शुरुआत सांस्कृतिक पहलों की एक श्रृंखला के साथ की, जिसमें विभिन्न जनभागीदारी गतिविधियाँ, देश भर के 75 शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक विशेष विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम, जी-20 लोगो और रंगों के साथ 100 एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) स्मारकों को रोशन करना और नागालैंड में होम्बिल उत्सव में जी-20 का प्रदर्शन शामिल है।

4. साहित्य की समीक्षा

जॉन स्मिथ (2022) द्वारा लिखित लेख "जी20 और भारतीय प्रेसीडेंसीः प्राथमिकताओं और चुनौतियों की समीक्षा" जी20 और इसके अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का पता लगाता है। इसमें जी20 के इतिहास, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के साथ-साथ पिछले जी20 प्रेसीडेंसी, भारत की भागीदारी और समूह में इसके योगदान को शामिल किया गया है। समीक्षा में भारत की अध्यक्षता के दौरान उसकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, इसकी पहलों, साझेदारियों और परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। लेख जी20 और वैश्विक शासन पर अकादमिक चर्चा में योगदान देता है। प्रबीर डे (2017) प्रबीर डे का लेख, "जी20 में भारत की भूमिका और स्थितिः एक आकलन," पिछले अध्ययनों, लेखों और रिपोर्टों की एक साहित्यिक समीक्षा है जो जी20 में भारत की भागीदारी और समूह के भीतर इसकी स्थिति पर चर्चा करती है। समीक्षा का उद्देश्य जी-20 में भारत की भूमिका से संबंधित प्रमुख विषयों, तर्कों और निष्कर्षों की पहचान करना है, जिसमें ऐतिहासिक भागीदारी, वैश्विक शासन में योगदान, जी-20 के भीतर प्रभाव, नीति प्राथमिकताएँ, पहल और अन्य सदस्य देशों के साथ इसके संबंध शामिल हैं। समीक्षा लेखक को अकादमिक चर्चा के भीतर अपने शोध को स्थापित करने, आगे की खोज के लिए अंतराल या क्षेत्रों की पहचान करने और अपने शोध के महत्व को स्थापित करने में मदद करती है। अंततः, समीक्षा जी-20 में भारत की भूमिका और स्थिति के लेखक के आकलन और विश्लेषण के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है, जो इस विषय पर मौजूदा ज्ञान में योगदान करती है। रेणु मोदी (2021) रेणु मोदी का लेख, "जी-20 और भारतीय अध्यक्षताः चुनौतियाँ और अवसर," इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ,

जी-20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में मौजूदा साहित्य और शोध पर केंद्रित है। समीक्षा का उद्देश्य इस भूमिका से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में मौजूदा ज्ञान और शोध अंतराल की पहचान करना है। इसमें जी-20 के उद्देश्यों, कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ वैश्विक शासन, आर्थिक नीतियों और विकास पर इसके प्रभाव जैसे विषयों को शामिल किया गया है। समीक्षा जी-20 की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करके शुरू होती है, इसकी स्थापना और प्रमुख मील के पत्थर पर प्रकाश डालती है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में जी-20 की प्रभावशीलता पर पिछले अध्ययनों की जांच करती है। यह ळ20 प्रेसीडेंसी के रूप में अलग-अलग देशों की भूमिका और वैश्विक एजेंडा पर उनके प्रभाव पर शोध का भी पता लगाता है। समीक्षा मौजूदा ज्ञान का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जो लेखक के विश्लेषण और क्षेत्र में योगदान के लिए आधार तैयार करती है। राजीव कुमार (2021) राजीव कुमार का लेख, " जी-20 में भारत का नेतृत्वः चुनौतियाँ और रणनीतियाँ," जी-20 के नेता के रूप में भारत की भूमिका से संबंधित मौजूदा विद्वानों के कार्यों और प्रकाशनों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। यह एक वैश्विक आर्थिक मंच के रूप में जी-20 के महत्व और इसके ढांचे के भीतर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव का पता लगाता है। समीक्षा में जी-20 में भारत के पिछले योगदान और नेतृत्व संभालने में आने वाली चुनौतियों, जैसे कि घरेलू प्राथमिकताओं को संतुलित करना और सदस्य देशों के बीच विविध हितों का प्रबंधन करना, की जांच की गई है। यह भारत के जी-20 एजेंडे को आकार देने में भारतीय थिंक टैंक और शिक्षाविदों की भूमिका पर भी जोर देता है और इसके घरेलू सुधारों और वैश्विक आकांक्षाओं के लिए भारत के नेतृत्व के निहितार्थों का विश्लेषण करता है। समीक्षा समन्वय और अनुसंधान सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होती है, साथ ही आगे के विश्लेषण के लिए क्षेत्रों का सुझाव देती है और भविष्य की भागीदारी के लिए सिफारिशें पेश करती है। कुणाल सेन (2021) कुणाल सेन का लेख, "भारत और जी-20ः संभावनाएँ और चुनौतियाँ," जी-20 में भारत की भागीदारी के लिए प्रासंगिक पिछले शोध और सिद्धांतों का अवलोकन प्रदान करता है। यह वैश्विक शासन में भारत की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में इसकी भागीदारी और जी-20 में इसकी सदस्यता के निहितार्थ जैसे विषयों की पड़ताल करता है। समीक्षा मौजूदा साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है, प्रमुख विषयों और

ज्ञान अंतरालों की पहचान करती है, और जी-20 के साथ भारत की भागीदारी पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है। यह वर्तमान ज्ञान के दायरे में लेखक के शोध के संदर्भ और महत्व को स्थापित करता है। के.एम. रमन (2021) के.एम. रमन का लेख, "भारत और जी20ः अपेक्षाएँ और निहितार्थ," जी20 में भारत की भागीदारी पर पहले से प्रकाशित शोध और विद्वत्तापूर्ण कार्यों का विश्लेषण और सारांश प्रदान करता है। यह विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों में भारत की ऐतिहासिक भागीदारी, जी20 के भीतर इसकी स्थिति और प्रभाव, इसकी नीतिगत प्राथमिकताएँ और समूह से अपेक्षाएँ, और इसकी भागीदारी के निहितार्थ। मौजूदा साहित्य की समीक्षा करके, लेखक संदर्भ स्थापित करता है, अंतराल की पहचान करता है, और क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का योगदान देता है। सचिन कुमार शर्मा (2021) सचिन कुमार शर्मा का जी20 की भारत की अध्यक्षता पर लेख जी20 में भारत की भूमिका से संबंधित मौजूदा अकादमिक कार्यों का अवलोकन प्रदान करता है। यह जी20 के इतिहास और उद्देश्य को कवर करता है, जी20 शिखर सम्मेलनों में भारत की पिछली भागीदारी का पता लगाता है, और इसकी अध्यक्षता के दौरान भारत को मिलने वाले लाभों और चुनौतियों की जांच करता है। समीक्षा निष्कर्षों का संश्लेषण करती है, ज्ञान में अंतराल की पहचान करती है, तथा लेख के आगामी विश्लेषण के लिए आधार तैयार करती है।

5. अध्ययन के उद्देश्यः

1. भारत में जी-20 की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करना। 2. भारत में जी-20 की अध्यक्षता के तहत, दुनिया की प्रमुख समस्याओं की पहचान करना और तदनुसार उन्हें संबोधित करने के लिए सुधारों पर चर्चा करना।

6. शोध पद्धति

अनुसंधान या इतिहासलेखन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं और इसे आम तौर पर वैज्ञानिक जांच के तरीकों में से एक के रूप में गिना जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन करना एकत्रित अनुसंधान सामग्री को एकत्रित करने और पढ़ने तथा एकत्रित आंकड़ों से पांडुलिपि लिखने की प्रक्रिया थी। इच्छाओं को अक्सर संग्रह करने, पढ़ने और लिखने के बीच आगे-पीछे करना पड़ता है। डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। द्वितीयक स्रोतः घटनाओं या लेखों के लिए स्रोतों के द्वितीयक स्रोतों का वर्णन किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो सीधे तौर पर घटना में शामिल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि

घटना घटित होने के काफी समय बाद घटना का वर्णन किया जाए। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत या दोनों के संयोजन से बनाए जा सकते हैं। इस शोध कार्य में शोधकर्ताओं ने मुख्य रूप से डेटा के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया है। इसके उपयोग किए गए स्रोतों में आज विभिन्न शोध रिपोर्ट, विभिन्न लेख और प्रकाशित पुस्तकें शामिल हैं जिन्हें ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

7. परिणाम एवं चर्चा

अब से, जी20 'लोकतंत्र की जननी' भारत के लिए अपने समस्त गौरव और विविधता को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी होगा, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट-अप तक लगभग हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत 56 विविध स्थानों पर जी20 से संबंधित 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा, जिससे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को इस जीवंत और वैविध्यपूर्ण देश का दौरा करने का अवसर मिलेगा। जी20 के कार्यक्रम अनेक आगंतुकों के लिए, भारत को अनुभव करने का पहला अवसर होंगे और इसलिए सभी भारतीयों को विश्व का स्वागत करने और उनके साथ एक परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्षित करने की आवश्यकता है। इस प्रवेशिका में भारत की जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रमुख विषयों पर संक्षिप्त विवरण शामिल किए गए हैं, जो अगले 12 महीनों में भारत द्वारा 20 सदस्य देशों वाले इस समूह का नेतृत्व संभालने के दौरान उसके प्रमुख केदिं्रत क्षेत्रों और प्राथमिकताओं से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अवगत कराएंगे। हमें उम्मीद है कि भारत विश्व को प्रभावित करने वाले के रूप में अपनी पहचान को दृढ़ बनाएगा तथा अधिक समावेशी और न्यायसंगत दुनिया बनाने की दिशा में प्रयासरत जी20 प्रक्रिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। ऽ ऊर्जा संक्रमण:पर्यावरण के अनुकूल विश्व को आकार देना वर्तमान में जारी भारत की नवीकरणीय क्रांति की प्रमुख प्राथमिकता कम कार्बन उत्सर्जन में तेजी लाते हुए ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है और यह भारत की जी20 की अध्यक्षता के एजेंडा का प्रमुख भाग होगी। नए मानदंड और लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत पहले ही घोषित कर चुका है कि उसकी आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित की जाएगी। भारत के अनुसार, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती वित्त तथा प्रौद्योगिकी की सतत आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में सीओपी-26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में समावेशी ऊर्जा परिवर्तन का अपना विज़न प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने

विश्व को "पंचामृतः (पांच अमृत तत्व)" की अवधारणा से अवगत कराया। इस पंच- आयामी योजना में शामिल हैं: ▪ भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ▪ भारत 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। ▪ भारत अब से 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा। ▪ भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा। ▪ भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। यह "पंचामृत" जलवायु कार्रवाई में भारत का अभूतपूर्व योगदान होगा। ऽ जलवायु वित्त और हरित वित्त भारत जी20 का सदस्य है और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समूह के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में जलवायु वित्त और हरित वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से जलवायु वित्त और हरित वित्त के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में काम कर रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच सहयोग का एक मंच है, जबकि ब्क्त्प् का लक्ष्य आपदा-रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देना है। भारत हरित जलवायु कोष और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष जैसी पहलों के माध्यम से हरित वित्त को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रहा है। ऽ सतत विकास भारत ने 2022 में जी20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक विश्व, एक परिवार" था। जी20 के पास आवश्यक ज्ञान, अनुभव और वित्तीय संसाधन हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर दिशा बदलने के लिए आवश्यक हैं। विकास कार्य समूह जी20 सदस्यों को एक मंच प्रदान करता है, जहाँ वे एक साथ आ सकते हैं, बहुपक्षवाद को प्राथमिकता दे सकते हैं, विकास को प्रोत्साहित करने वाले विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, विकास रणनीतियों का पुनर्गठन कर सकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। जी20 ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर एक कार्य योजना भी विकसित की है। भारत जी20 का सदस्य है और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ अपने काम को और अधिक संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी उन्मूलन, सतत विकास प्राप्त करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे। जी20 ने

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के भाग के रूप में विकास के लिए वित्तपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन का समर्थन करने का वचन दिया है। जी20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां इसका तुलनात्मक लाभ है और आर्थिक सहयोग के लिए वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी20 का तुलनात्मक लाभ इसकी संयोजक शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की सामूहिक क्षमता में निहित है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शामिल है, और एक वैश्विक सक्षम वातावरण बनाना है। भारत 2008 से जी20 बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत अपनी स्थापना के समय से ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक मजबूत समर्थक रहा है। भारत स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। ऽ बुनियादी ढांचे का विकास भारत प्रौद्योगिकी के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर कर सकता है; वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, और कृषि से लेकर शिक्षा तक के उद्योगों में तकनीक-सक्षम विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकता है। ऽ कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण जी20 कृषि मंत्रियों ने दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। वे टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, खाद्य प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन और अन्य झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत जी20 का सदस्य है और उसने इन प्रयासों में भाग लिया है। ऽ मानव संसाधन विकास जी20 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास पहल। हालाँकि, जी20 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (बीस का समूह - जी20) के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जी20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ इसका तुलनात्मक लाभ है और आर्थिक सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी20 का तुलनात्मक लाभ इसकी संयोजक शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की इसकी सामूहिक क्षमता में निहित है। ऽ रोजगार जी20 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ अपने

काम को और अधिक संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को प्राप्त करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे। जी20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ इसका तुलनात्मक लाभ है और आर्थिक सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी20 का तुलनात्मक लाभ इसकी संयोजक शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की सामूहिक क्षमता में निहित है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शामिल है, और वैश्विक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जी20 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ अपने काम को और अधिक संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को प्राप्त करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे। जी20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां उसे तुलनात्मक लाभ है और जो आर्थिक सहयोग के लिए वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी20 का तुलनात्मक लाभ इसकी आयोजन शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की सामूहिक क्षमता में निहित है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शामिल है, और वैश्विक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है। ऽ औद्योगिकीकरण सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर जी20 कार्य योजना। जी20 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ अपने काम को और अधिक संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी उन्मूलन, सतत विकास को प्राप्त करने और सभी के लिए एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के हमारे प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे। जी20 2030 एजेंडा के उन क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां इसका तुलनात्मक लाभ है और आर्थिक सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में मूल्य जोड़ सकता है। समग्र सतत विकास एजेंडे के भीतर, जी20 का तुलनात्मक लाभ इसकी आयोजन शक्ति और उच्चतम वैश्विक स्तर पर पहलों को अपनाने और उनका समर्थन करने की सामूहिक क्षमता में निहित है, जिसमें मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शामिल है, और वैश्विक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है। सतत विकास के लिए जी20 सामूहिक कार्रवाइयां विकास पर जी20 के दीर्घकालिक प्रयासों, इसके आर्थिक फोकस और वैश्विक

चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामूहिक ताकत को दर्शाती हैं और सतत विकास से तेजी से जुड़ी हुई हैं। मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए जी20 एजेंडा और जी20 के बहुवर्षीय विकास एजेंडा (सियोल विकास सहमति, सेंट पीटर्सबर्ग विकास आउटलुक और जी20-कम आय और विकासशील देशों की रूपरेखा) पर आधारित, ये एसडीएस 2030 एजेंडा में संबोधित किए गए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों और गरीबी उन्मूलन में सतत विकास की दिशा में जी20 की सामूहिक कार्रवाइयों को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, एसडीएस यह मानता है कि सभी जी20 कार्यप्रवाहों में 2030 एजेंडा को साकार करने में योगदान करने की क्षमता है और इन्हें उभरती प्राथमिकताओं के अनुसार और विकसित किया जाएगा। 8. निष्कर्ष भारत ने 2 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से कार्यभार ग्रहण करते हुए समूह 20 की अपनी एक साल की अध्यक्षता शुरू की, जो भू-राजनीतिक उथल-पुथल और महामारी के बाद की रिकवरी को लेकर अनिश्चितता के समय था। भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय "लोग, ग्रह और समृद्धि" है। जी20 अध्यक्षता भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने और वैश्विक सॉफ्ट पावर बनने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। भारत की ळ20 अध्यक्षता दुनिया में सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और संधारणीय भविष्य की होगी। थीम में प्रधानमंत्री के पर्यावरण के लिए जीवनशैली या स्पथम् के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, जो एक हरित और नीले भविष्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होने वाले संधारणीय और जिम्मेदार विकल्प बनाने की आवश्यकता से जुड़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अर्गुएलो, जॉर्ज, एड. (2024)। जी20 में अमेरिकियों से पैसा कमाना। स्यूदाद ऑटोनोमा डी ब्यूनस आयर्सः फंडासियोन एम्बाजदा एबिएर्टा।
2. बेने, निकोलस (2003), " इवियन शिखर सम्मेलन की छाप, 1-3 जून 2003 ," जी8 रिसर्च ग्रुप।
3. बेने, निकोलस (2004). "2005 जी8 ग्लेनेगल्स शिखर सम्मेलन की संभावनाएँ।" जी8 अनुसंधान समूह को प्रस्तुति, टोरंटो विश्वविद्यालय, 22 नवंबर।
4. बर्गस्टेन, सी.एफ. (2004). "जी20 और विश्व अर्थव्यवस्था।" जी20 के प्रतिनिधियों को वक्तव्य। लीपज़िग, जर्मनी, 4 मार्च, 2004. विश्व अर्थशास्त्र 5 (3)ः 27-36.
5. बर्टेल्समैन फाउंडेशन (2018)। जी20 देशों के नागरिकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मजबूत समर्थन। नीति संक्षिप्त, 22 नवंबर।
6. ब्रैडफोर्ड, कोलिन और जोहान्स लिन (2004)। "वैश्विक आर्थिक शासन एक चैराहे परः जी7 को जी20 से बदलना।" ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन पॉलिसी ब्रीफ 131 (अप्रैल)।

7. ब्रैडलो, डैनियल डी. (2016). "फ्रंटलाइन से सबकः जी20 में मेरी भागीदारी से मैंने क्या सीखा।" ग्लोबल समिट्री , जनवरी। कवपः 10.1093/हसवइंस/हनअ007.

8. ब्रेटरस्की, मैक्सिम (2014)। " क्या वैश्विक शासन मौजूद है?, " जॉन किर्टन के ग्लोबलाइज्ड वल्ड के लिए जी20 शासन की समीक्षा। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन रिसर्च जर्नल , खंड 9, अंक 4, पृष्ठ 115-116, 2014।

9. ब्रेन, डोनाल्ड जे.एस. (2009). " एपीईसी के 20 वर्ष पूरे होने और वित्तीय सुनामी की वर्षगांठ ।" ऑल चाइना इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस में समापन भाषण, हांगकांग, 16 दिसंबर।

10. ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन (2013). " थिंक टैंक 20ः अपरंपरागत मौद्रिक नीति की नई दुनिया में जी-20 और केंद्रीय बैंक ," अगस्त.

11. ब्रायंट, राल्फ सी. (2003). टर्बुलेंट वाटर्सः क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंस एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस . वाशिंगटन डीसीः ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट प्रेस.

12. कैलाघन, माइक (2014). " अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिखर सम्मेलनः क्या वे प्रयास के लायक हैं? ", कैरेबियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी 2(3)ः पृ. 111-123.

13. कैलाघन, माइक, एड. (2014). थिंक20 2014ः ऑस्ट्रेलिया की जी20 प्रेसीडेंसी पर प्रगति रिपोर्ट . सिडनीः लोवी इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी. 1

4. कैलाघन, माइक, और ह्यूग जॉर्गेनसन (2013)। थिंक 20 पेपर्स 2014ः ब्रिस्बेन जी20 शिखर सम्मेलन के लिए नीतिगत सिफारिशें । सिडनीः लोवी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी।

15. पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा पैनल (2022)। " एमडीबी की निवेश क्षमता को बढ़ावा देना ।" बहुपक्षीय विकास बैंकों की पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा की एक स्वतंत्र समीक्षा। 2020 इतालवी और 2022 इंडोनेशियाई जी20 प्रेसीडेंसी के समर्थन से प्रकाशित।

16. कैरिन, बैरी (2005). "वैश्विक स्तर पर परिवर्तन लाना।" जॉन इंग्लिश, रमेश ठाकुर और एंड्रयू एफ. कूपर, संपादक। शीर्ष से बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारः एक लीडर्स 20 शिखर सम्मेलन । टोक्योः संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय प्रेस।

17. चिन, ग्रेगरी और ह्यूगो डॉब्सन (2015). " चीन 2016 में जी20 मेज़बान के रूप मेंः एशियाई वैश्विक नेतृत्व की शुरुआत? " वैश्विक नीति (ब्लॉग). 3 मार्च.

18. चिन, ग्रेगरी और ह्यूगो डॉब्सन (2016)। "चीन की जी20 हांग्जो की अध्यक्षताः वैश्विक नेतृत्व और रणनीति पर," ग्लोबल समिट्री मार्च 2016।

19. चोई, वोंगी (2010). " जी20 प्रक्रिया और सियोल शिखर सम्मेलन में कोरिया की भूमिका ।" कोरियाई एसोसिएशन ऑफ नेगोशिएशन स्टडीज द्वारा आयोजित "जी20 सियोल शिखर सम्मेलनः संकट से सहयोग तक" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार किया गया पेपर, 20 मई, 2010, सियोल, कोरिया।

20. क्रिस्चियन, एलिसन (2017). "ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (कर में भूमिका)," एल्गर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ में , थॉमस कॉटियर और क्रिस्टा नादाकावुकरन शेफर द्वारा संपादित (चेल्टेनहैम, यूके; नॉर्थम्प्टन, एमए, यूएसएः एडवर्ड एल्गर, पृ.111-112.

21. क्लब ऑफ मैड्रिड (2011)। " संकट के बाद की दुनिया में जी20 की भूमिकाः मुख्य संदेश / एल रोल डेल जी20 एन अन मुंडो पोस्ट-संकटः मेन्सजेस पिंरसिपल्स ।" पेरिस, 9 सितम्बर।

22. क्लब ऑफ मैड्रिड (2010)। " संकट के बाद की दुनिया में जी-20 की भूमिका । " क्लब ऑफ मैड्रिड, थ्प्क्म् और कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा एक परियोजना की अंतिम रिपोर्ट। मैड्रिड।

23. कूपर, एंड्रयू एफ. (2007). "जी8 सुधार के लिए बी(आर)आईसीएसएएम मॉडल का तर्क।" अंतर्राष्ट्रीय शासन में सीआईजीआई नीति संक्षिप्त 1 (मई)ः 1-11.

24. कूपर, एंड्रयू एफ. (2014). " जी20 और विवादित वैश्विक शासनः ब्रिक्स, मध्य शक्तियां और छोटे राज्य ," कैरेबियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी 2(3)ः पृ. 87-109.

25. कूपर, एंड्रयू एफ. और केली जैक्सन (2007)। "वैधता पुनः प्राप्त करनाः जी8 और 'हेलीगेंडम प्रक्रिया।" सीआईआईए इंटरनेशनल इनसाइट्स (जुलाई)।

Corresponding Author: Rekha Sirohi
E-mail: rs.9897128444@gmail.com
Received: 11 December, 2024; Accepted: 20 December, 2024. Available online: 30 December, 2024
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License